



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

की

2026-27 के लिए

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

OUTPUT-OUTCOME MONITORING FRAMEWORK

OF

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

FOR

2026-27

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधारों (स्मार्ट पीडीएस) के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गत 2026-27			परिणाम 2026-27		
	निर्गत	निर्गत संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	परिणाम संकेतक	लक्ष्य 2026-27
मार्च, 2026 के बाद संभावित विस्तार के लिए वर्तमान में इस योजना की समीक्षा की जा रही है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।	1. स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन। संपूर्ण प्रणाली का अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन।	1.1 अंचलवार कार्यान्वयन (संख्या में)	9	1. मार्च, 2026 तक 36 राज्यों में इसके कार्यान्वयन की शुरुआत	1.1 राज्यों में स्मार्ट पीडीएस का परिनियोजन (संख्या में)	पहली तिमाही: 36 दूसरी तिमाही: 0 तीसरी तिमाही: 0 चौथी तिमाही: 0
	2. लाभार्थियों की बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देते हुए आधार-प्रमाणित खाद्यान्न वितरण, वर्तमान में यह कवरेज 97% है।	2.1 आधार प्रमाणित वितरण में वृद्धि (प्रतिशत में)	पहली तिमाही - 0.5 दूसरी तिमाही - 1 तीसरी तिमाही - शून्य चौथी तिमाही - शून्य	2. खाद्यान्न के लीकेज को कम करना और यह सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न लक्षित आबादी तक पहुंचे, जिससे सटीकता और पारदर्शिता में सुधार हो।	2.1 अनधिकृत या डुप्लिकेट वितरण के मामलों में कमी। (प्रतिशत में)	100 पहली तिमाही -0.25% दूसरी तिमाही - 0.25% तीसरी तिमाही - 0.25% चौथी तिमाही - 0.25%
		2.2 प्रमाणित लेन-देन के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की मात्रा (लाख टन में)	पहली तिमाही -121.29 दूसरी तिमाही -121.17 तीसरी तिमाही -121.30 चौथी तिमाही -121.54		2.2 वितरण दक्षता में सुधार। (प्रतिशत में)	

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गत 2026-27			परिणाम 2026-27		
	निर्गत	निर्गत संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	परिणाम संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	3. एनएफएसए लाभार्थियों का उचित लक्ष्यीकरण।	3.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पारिस्थितिकी तंत्र में अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई/निष्कासन (प्रतिशत में) चिह्नित लाभार्थी: 8.51 करोड़ लक्ष्य कार्रवाई (निष्कासन और पात्र पाए गए लाभार्थी): 100%	पहली तिमाही : 60% दूसरी तिमाही : 15% तीसरी तिमाही : 15% चौथी तिमाही : 10%	3. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा परिभाषित समावेशन/बहिष्करण मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना।	3.1 चिह्नित लाभार्थियों पर की गई कार्रवाई (प्रतिशत में)	100